



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 26 जून, 2012/5 आषाढ़, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA.-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st June, 2012

No. HHC/GAZ/14-58/75-XII.—The result of 58th Departmental Examination of the Civil Judges (Members of the Himachal Pradesh Judicial Service) held in December, 2011 is hereby published for information of all concerned as required under rule 2 read with Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 and Regulation 17(xi) of the Himachal Pradesh Judicial Service (Departmental Examination) Regulations, 2004.

By order,
Sd/-
Registrar General.

RESULT OF 58TH DEPARTMENTAL EXAMINATION OF THE CIVIL JUDGES (JUNIOR DIVISION) HELD IN THE MONTH OF DECEMBER, 2011.

Note: 'WITH CREDIT (WC)' means passed by obtaining 3/4th of the maximum marks, 'HIGHER STANDARD (HS)' means passed by obtaining 2/3rd of the maximum marks, 'LOW STANDARD (LS)' means passed in the lower standard by obtaining 50% marks. 'A' means 'Absent' and 'F' means 'Fail'.

Sr. No.	Name of the Officer.	Roll No.	Group A-I Criminal Law (120 marks)	Group A-II Civil Law (120 marks)	Group B Revenue Law-I & Revenue Law-II (120 marks each, 240 marks)	Group-C Accounts (160 marks)	Group-D Constitutional Law (100 marks)	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Sh. Surya Parkash	101					84 (WC)	
2.	Sh. Amardeep Singh	102	88 (HS)				73 (HS)	
3.	Sh. Sunish Aggarwal	103					71 (HS)	
4.	Sh. Sandeep Singh Sihag	104		62 (LS)		114 (HS)	77 (WC)	
5.	Ms. Akshi Sharma	105	94 (WC)			110 (HS)	'A'	
6.	Sh. Aslam Beg	106	81 (HS)			108 (HS)		
7.	Ms. Neha Sharma	107	80 (HS)	71 (LS)	59 } } 140 (LS) 81 }	107 (HS)	80 (WC)	
8.	Ms. Manisha Goyal	108	80(HS)	82 (HS)	63 } } 138 (LS) 75 }	119 (HS)	83 (WC)	
9.	Ms. Upasna Sharma	109	89 (HS)	80 (HS)	61 } } 137 (LS) 76 }	111 (HS)	81 (WC)	
10.	Sh. Vishal Bhamnotra	110	64 ½ (LS)	72 (LS)	50 ½ } } 116 ½ (F) 66 }	107 (HS)	69 (HS)	

(B.M. Gupta)
Addl. Registrar (Estt. & GAD)
Superintendent Examination

(A.C. Dogra)
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th June, 2012

No. HHC/Admn. 16 (21) 75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297 (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5 (vi) of the H. P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Sumit Sharma, Ms. Meghna Kashava and Sh. Sushant Vir Singh Thakur, Advocates of H. P. High Court as Oath Commissioners for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla, with immediate effect, for a period of two years, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 21st June, 2012*

No. HHC/GAZ/14-202/90-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 23 days earned leave w.e.f. 11.6.2012 to 3.7.2012 with permission prefix second Saturday and Sunday falling on 9th and 10th June, 2012 already sanctioned vide this Registry notification of even number dated 6.6.2012 in favour of Shri Ram Krishan Sharma, Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P.

By order,
Sd/-
Registrar General.

पशुपालन विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 23 जून, 2012

संख्या: ए.एच.वाई.-ए(3)-6/2009.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, संयुक्त निदेशकए वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियमए 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) अधिसूचना संख्या: ए0एच0वाई0-ए(3)1/2002 तारीख 26 सितम्बर, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव (पशुपालन)।

हिमाचल प्रदेश, पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक, वर्ग—I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—संयुक्त निदेशक, पशुपालन।
2. पद (पदों) की संख्या.—3 (तीन)।
3. वर्गीकरण.—वर्ग—I (राजपत्रित)।
4. वेतनमान.—पे बैंड 37400—67000/—रूपए जमा 8700/—रूपए ग्रेड पे।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—चयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—लागू नहीं।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—लागू नहीं।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु: लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं।
9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—उप निदेशक, पशुपालन में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप निदेशक, पशुपालन में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उप निदेशक और सहायक निदेशक, पशुपालन के रूप में संयुक्ततः तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके, तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप निदेशक (पशुपालन) के रूप में एक वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य है :

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्वीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी तथा भरमौर का उपमण्डल ।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किनौर ।
8. सिरमौर जिले में उप तहसील कमरु के कठबाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त एवं शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृत्त ।
9. जिला मण्डी की करसोग तहसील का खनयोल-बागडा पटवार वृत्त, बालीचौकी उप-तहसील के गाडा गुसैनी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खुलानाला, पद्धर तहसील के झारवाड़ कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, शिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरड़ और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बागडा, उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत्त एवं सुन्दरनगर तहसील का वटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्म्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हैं या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हैं।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्, जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Ahy-A(3)-06/2009 dated 23.06.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd June, 2012

No. Ahy-A(3)-06/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for

the post of Joint Director, Class-I (Gazetted), in the Department of Animal Husbandry, Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely :-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Animal Husbandry Department, Joint Director, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the e-Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Animal Husbandry Department Joint Director, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2002 notified vide notification No. Ahy-A (3)-1/2002 dated 26th September, 2002 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under subrule-2 (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (AH).

ANNEXURE-I

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR, CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the post.**—Joint Director, Animal Husbandry.
- 2. Numbers of posts.**—3 (Three).
- 3. Classification.**—Class-I (Gazetted).
- 4. Scale of pay.**—Pay Band ₹ 37400-67000 + ₹ 8700/- Grade Pay.
- 5. Whether selection post or Non-selection post.**—Selection.
- 6. Age for direct recruitment.**—Not applicable.
- 7. Minimum Education and other qualification required for direct recruits.**—Not applicable.
- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s).**—Age : Not applicable. *Educational Qualification:* Not applicable.
- 9. Period of probation, if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100 % by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—“By promotion from amongst the Deputy Directors, Animal Husbandry, having two years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Deputy Directors, Animal Husbandry with 3 years regular service or regular combined as Deputy Director and Assistant Director, Animal Husbandry out of which 01 year essential service as Deputy Director (Animal Husbandry).

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas :

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials, who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult areas, shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

EXPLANATION-I.—For the purpose of proviso (I) supra the term in Tribal/Difficult Areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under :-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh,

Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kallapar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules;

Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall process the minimum qualifying service of atleast 03 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, which ever is less.

Provided further that where a person becomes in eligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal State Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental promotion committee, exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HP PSC is to be consulted in making recruitments.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd June, 2012

No. EDN-A-Ka(1)-2/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of new Government Degree College in Kotla-Behr, Tehsil Jaswan, Distt. Kangra, H.P. with immediate effect, in public interest.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary(Education).

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 26th June, 2012

No. Rev. B.A.(3)-1/2004-Vol-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to substitute Chapter 14 of the Himachal Pradesh Land Records Manual, 1992 notified vide notification No. Rev. (LR) A (58)/89 dated 3rd December, 1992, as follows:-

“14.1. Entitlement to apply for partition.—(1) Any joint owner may apply for partition if-

- (a) his share is entered in the last record-of-rights; or
- (b) his right to a share has been established by decree of Court; or
- (c) his title has been admitted in writing by all persons interested in the admission or denial thereof.

(2) Partition can be either private partition with mutual consent of the parties or any one or more parties may apply for partition under Chapter-IX of the H.P. Land Revenue Act, 1954.

14.2. Authorities competent to decide partition matters.—Assistant Collectors of either grade are competent to hear and decide applications of partition in their jurisdiction except when a question of title is required to be decided for which the Assistant Collector of the First Grade alone is competent. During the settlement operation the partition cases will be heard and disposed of by the Settlement Tehsildar and Naib Tehsildar exercising powers of Assistant Collector of either grade except when a question of title is required to be decided by Assistant Collector of 1st Grade. In case the revenue estate is de-notified from settlement under section 33 (9) of the HP Land Revenue Act prior to completion of the proceeding the case will be transferred to the successor in office i.e. Tehsildar/Naib Tehsildar Mohal.

14.3. Private partition.—On written application duly signed by all the shareholders, the Patwari shall record a voluntary partition for orders in the mutation register. Alternately, all or any shareholders may jointly or otherwise present an application in the office of the Revenue Officer seeking attestation of mutation based on the details in the application. In either case, the Revenue Officer shall explain the details of partition sought by the applicants to all shareholders after ensuring they are all present in person or through power of attorney and having satisfied himself that their consent is freely given, he shall proceed to attest the mutation. In case all shareholders are not present or there are grounds to believe that the partition is unfair to some parties or objected to by one or more shareholders or their consent has been obtained by coercion or unfair means, he shall reject the same.

14.4 Documents to accompany Application for partition under chapter IX of the H.P. Land Revenue Act, 1954.—Following documents should be attached with the application for partition:-

1. An extract from the last detailed jamabandi, giving the complete entry for the holding or holdings of which partition is desired.
2. A note of any mutations attested after the filing of the last detailed jamabandi should be added.

14.5. Partition Procedure.—All parties interested shall be summoned by the competent Revenue Officer to appear on a date fixed for hearing of the partition application. If they are so numerous that personal service on each of them is not reasonably practicable, the procedure laid down in section 21 (3) and 23 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act shall be followed. The summons and proclamations may be issued simultaneously. When the requirements of the law as regards the service of summons have been complied with, and the Revenue Officer is satisfied that all interested parties have had an opportunity of being present, he should proceed with the hearing on the date fixed putting on the file a note of the names of any parties who have not appeared.

14.6. Admission or disallowance of partition.—After examining the interested parties, the Revenue Officer may disallow the application, if he finds sufficient reasons to do so and record the same on the file. If the Revenue Officer has no reasons to disallow the application he shall ascertain whether a dispute exists regarding the partition between any of the interested parties. The disputes so arising may be of two kinds:-

- (i) A question as to title in the property of which partition is being sought.
- (ii) Other questions regarding the mode of making the partition.

14.7. Preliminary enquiry where question of title are raised.—If during the course of partition proceedings, an objection is raised by one of the parties that the question of title is

involved, the Revenue Officer can not ignore such objection. He shall make preliminary enquiry and if he comes to the conclusion that such question of title is really involved, he should invoke the provisions of section 129 of H.P. Land Revenue Act, 1954; and proceed accordingly. Mere raising of question of title does not make it incumbent upon the Revenue Officer to accept it as he has to ascertain and determine whether a question of title is involved or not. Detailed reasons for admitting or rejecting such a claim should be given in an order on this issue. Examples of disputes as to question of title are-

- (a) The respondent/s denies the correctness of entry in the record-of-rights and there are sufficient reasons for considering such a plea.
- (b) The respondent/s admits the correctness of the entry in the record-of-rights, but raises a plea of adverse possession against the applicant.
- (c) The respondent claims an exclusive title on the land or part thereof on the basis of some document which, according to him, bears a legal sanctity.

14.8. When there are disputes as to title.—If the application is being heard by the Assistant Collector of IInd Grade and it appears to him that there is dispute as to question of title, which must be dealt with in the manner laid down in section 129, he should record clearly what the points in issue are, and send the case for the orders of the Assistant Collector of Ist Grade who is competent to decide it. The Assistant Collector of Ist Grade may either decide such question personally as per provisions of Section 129 or ask the parties to get it decided from a court of competent jurisdiction.

14.9. Preparation statement of share and possession.—In the partition proceeding where no question of title is involved or the question has been decided by the Assistant Collector First Grade or court of competent jurisdiction, the Revenue Officer shall, fix the case for the next hearing within the next one month and in the meantime, he shall cause the Field Kanungo, with the help of the Halqua Patwari, to get prepared statement/s of the current status on the ground (each khasra no. or part thereof) depicting the classification of land as per record (each khasra number or part thereof), shares of each party as per ownership, their actual possession, value of the land (each khasra number or part thereof). Any other details deemed important by the Kanungo can also be given in this statement/s. He shall forward the 'statement/s' alongwith his report thereon to the Revenue Officer before the next date of hearing.

14.10. Mode/manner of and order of Partition.—On receipt of statement/s, the Revenue Officer before whom the application has been filed shall have a copy of the statement/s given to each of the parties and hear objections if any in the matter. The Revenue Officer shall pass a speaking order on any objections received after such further inquiry as deemed appropriate by the Revenue Officer.

The Revenue Officer will then bring up issues that he is required to address in carrying out the partition and the mode in which he proposes to address them. Some examples of such issues are:

- (a) possession of land/values disproportionate to share.
- (b) possession disproportionate with regard to more valuable land.
- (c) Value addition to land by some cosharer by development of the same.

- (d) Compensating a cosharer who has developed land and added to its value. Such Compensation may be got evaluated from the technical expert in the concerned field, in case it appears necessary to do so.

Having listed the issues required to be addressed, the Revenue Officer shall proceed to outline the mode of partition *i.e.* manner in which he will address these issues. In drawing up the mode of partition the Revenue Officer shall take into account the following guidelines:-

- (i) Any conditions regarding partition in the village administration paper of the concerned revenue villages shall be specified;
- (ii) The land to be partitioned shall be pooled and thereafter valued keeping in view its distance from road, yield per unit per year in monetary terms on the basis of kinds of crops grown, value of trees standing on the land, any other potential usage of the land especially commercial use, etc.
- (iii) Taking into account above valuation and the factors like actual possession, efforts at development by specific shareholders, etc. the Revenue Officer shall make an equitable partition of the value of the land.
- (iv) In addressing these issues, the Revenue Officer will, if required, ask certain shareholders to monetarily compensate others.
- (v) how shamlat land is to be distributed shall be specified;
- (vi) any other factor which the revenue officer has considered necessary for purpose of carrying out the partition shall be mentioned.
- (vi) The Revenue Officer will ensure that a proper path/road/access is provided to all co-sharers for proper approach of individuals/cattle/agricultural machinery and equipments including tractors mainly where cultivation is being done with tractors.

After informing the parties present of the mode/manner in which he proposes the partition, the Revenue Officer will record and consider objections, if any, of the parties and decide the objections by a speaking order.

14.11 Draft Instrument of Partition.—Based on the principles enumerated in the mode of partition, as finalised after hearing objections, the Revenue Officer shall frame a draft instrument of partition and communicate the same to the parties and invite objections, if any, on this draft. In case, any party raises an objection on the share/land being allotted to him/her, the Revenue Officer will, decide the objection/s by a reasoned order. In case he is of the opinion that it is necessary to carry out a demarcation of the land in order to resolve the dispute he will direct a demarcation of the land on the spot and will decide the claim of the objector after receiving a report in the matter.

14.12. Final Instrument of Partition.—After passing orders on any matter arising out of para 14.11 and the expiry of time limit for filing of appeal, and no appeal being preferred, or after any appeal has been preferred and has been decided, a final instrument of partition shall be drawn upon stamp paper by the Revenue Officer. The date on which the partition is to take effect must be noted.”

By order,
Sd/-

Principal Secretary (Revenue).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जून, 2012

संख्या: रैव0 बी.ए. (3) 7/2010-I.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 के क्रम में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजस्व विभाग से सम्बन्धित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और नियत समय-सीमा को निम्न प्रकार से अधिसूचित करती हैं:—

सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
विभिन्न राजस्व न्यायालयों/कार्यालयों में स्थापित कॉपिंग ऐजेन्सी द्वारा अभिलेखों की प्रतियों का प्रदाय।	प्रभारी अधिकारी	एक सप्ताह	अधिकारी जिसके अधीनस्त प्रभारी अधिकारी है।

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव (राजस्व)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.Rev.B.A.(3)-7/2010-I dated 22nd June, 2012 as required under article 348(3) of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 22nd June, 2012

No. Rev. B.A. (3)-7/2010-I.—In continuation of this department notification of even number dated 20th December, 2011, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011, is pleased to notify the services, designated officers, first appellate authority and stipulated time limits pertaining to revenue department, for the purpose of Act *ibid*, as follows:

Services	Designated Officer	Time limit	First appellate Authority
Supply of copies from copying Agencies established in various Revenue Courts/Officers.	Officer-in-Charge.	One week.	Officer to whom Officer-in-charge is subordinate.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Revenue).

ब अदालत श्री धर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 10/चुराह/तह०/रीडर/2012

तारीख दायरा : 6-6-2012

श्री निजामद्दीन सुपुत्र श्री गुलामा, निवासी गांव सौहण्डा, परगना बगोड, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि० प्र०) . . सायल।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम निजामद्दीन है जोकि ग्राम पंचायत थनेईकोटी के रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल सौहण्डा में उसका नाम नबाबद्दीन दर्ज है। अतः वह अपना नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि निजामद्दीन सुपुत्र श्री गुलामा, निवासी गांव सौहण्डा, परगना बगोड, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि० प्र०) के नाम दुरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-7-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश करें अन्यथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

धर्म सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, चुराह,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**Before the Sub-Divisional Magistrate, Kalpa Sub-Division at Reckong-Peo, District Kinnaur
Himachal Pradesh**

In the matter of :

Shri Avinash s/o Shri Bhag Sukh, r/o Village Sangla, Tehsil Sangla, District Kinnaur (H. P.)
. . Applicant.

Application for registration of marriage under the H. P. Registration of Marriages Act, 1996.

Notice to general public.

The above named applicant has preferred an application supported by an affidavit stating therein that he got married to Smt. Sandesha Kumari d/o Shri Lal Sukh, r/o Village & P.O. Jiskoon, Tehsil Dodra Kwar, District Shimla (H. P.) on 14-7-2010 as per prevalent customs, but name of his wife has not been entered in the records of Gram Panchayat Sangla so far and has further requested to issue an order to the Gram Panchayat Sangla for entry of the same.

Therefore, general public is hereby issued a notice through this publication that if anybody has any objection for the entry of name of Smt. Sandesha Kumari as wife of Shri Avinash s/o Shri Bhag Sukh, r/o Village Sangla, Tehsil Sangla, District Kinnaur (H. P.) in the records of the Gram Panchayat Sangla, he/she may present written/oral objection before the undersigned on or before 14-7-2012 failing which it will be presumed that nobody has any objection and necessary orders will be issued to the concerned Gram Panchayat for entry of the marriage.

Issued under my hand and seal of the Court today on 15th day of June, 2012.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Kalpa Sub-Division at Reckong-Peo,
District Kinnaur (H. P.).*

ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कमला उर्फ गुलाबी पत्नी श्री लोवजंग तनडुप, निवासी गांव बडाग्रां विहाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त वराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कमला उर्फ गुलाबी पत्नी श्री लोवजंग तनडुप, निवासी गांव बडाग्रां विहाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बडाग्रां में गुलाबी देवी दर्ज है, जोकि गलत है और पहचान—पत्र में कमला दर्ज है जिसकी वह दरुस्ती करके पंचायत में कमला रखना चाहती है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे। आवेदिका ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम पंचायत में गुलाबी के स्थान पर कमला दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कमला के नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-7-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री तेनजिन ज़ामजो उर्फ अजय पुत्र श्री लोवजंग तनडुप, निवासी गांव बडाग्रां विहाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त वराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तेनजिन ज़ामजो उर्फ अजय पुत्र श्री लोवजंग तनडुप, निवासी गांव बडाग्रां विहाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बडाग्रां के परिवार रजिस्टर में अजय दर्ज है, जोकि गलत है और स्कूल प्रमाण—पत्र में तेनजिन ज़ामजो दर्ज है जिसकी वह दरुस्ती करके तेनजिन ज़ामजो रखना चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे। आवेदक ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम पंचायत में अजय के स्थान पर तेनजिन ज़ामजो दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तेनजिन के नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-7-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रमन गरसंन्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री खत्री राम तोमर पुत्र श्री रंगी लाल तोमर, निवासी गृह संख्या 263/1, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री खत्री राम तोमर पुत्र श्री रंगी लाल तोमर, निवासी गृह संख्या 263/1, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी

पुत्री प्रियंका तोमर का जन्म दिनांक 24-4-1991 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रियंका तोमर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-7-2012 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रमन गरसंन्गी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
16/2012	8-6-2012	Pending for 16-7-2012

Shri Om Parkash s/o Shri Hari Dutt, resident of Village Patiyana, P.O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

.. Applicant.

Versus

General public

.. Respondents.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Om Parkash s/o Shri Hari Dutt, resident of Village Patiyana, P.O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents that his son Gautam Attri born on 17-4-2007 at Village Patiyana, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat birth and death record, Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Gautam Attri may submit his objection in writing in this court on or before 16-7-2012 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after *expiry* of date.

Given under my hand and seal of the court on this 8th day of June, 2012.

Seal.

LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.